संपूर्ण बेंच

न्यायमूर्ति पी. सी. जैन, एस. सी. मित्तल और डी. एस. तेवतिया के समक्ष

हरद्वारी लाल कुलपति,-याचिकाकर्ता
बनाम
चांसलर एम. डी. विश्वविद्यालय और अन्य,-प्रतिवादी
1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 3385
16 नवंबर 1979.

रोहतक विश्वविद्यालय अधिनियम (1975 का 25)-धारा 8 और 9-रोहतक विश्वविद्यालय के प्रथम क़ानून-कानून 2, 3(1), 4 और 5 पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट (1807 का एक्स)-धारा 14- निलंबन का आदेश, चाहे आकस्मिक रिक्ति का परिणाम हो-चांसलर, क्या कुलपति को निलंबित करने के लिए सक्षम है, जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच सुविधा के लिए कुलपति का निलंबन ऐसी पूछताछ-क्या कानूनी है।

माना गया कि रोहतक विश्वविद्यालय के प्रथम क़ानून 4 के खंड (8) में आकस्मिक रिक्ति होने पर आमतौर पर कुलपति की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है। ऐसी नियुक्ति केवल नए कुलपति की नियुक्ति तक ही रहती है। एक आकस्मिक रिक्ति तब होती है जब वह किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर अस्तित्व में आती है, अर्थात, मृत्यु, इस्तीफे, निष्कासन या अन्यथा, एक आकस्मिक रिक्ति होती है और बनाई नहीं जाती है। यदि ऐसा है, तो निलंबन के आदेश के परिणामस्वरूप कोई आकस्मिक रिक्ति अस्तित्व में नहीं आएगी क्योंकि निलंबन के आदेश के परिणामस्वरूप केवल कार्यालय, पद या किसी के विशेषाधिकार से अस्थायी रूप से वंचित होना पड़ेगा। निलंबन आदेश के परिणामस्वरूप कोई पद रिक्त नहीं होता है। निलंबन का प्रभाव केवल उस व्यक्ति से उस कार्य को छीनना है जो उससे करना आवश्यक है। यदि निलंबन का आदेश देकर किसी पद पर नियुक्ति समाप्त नहीं की जाती है, तो क़ानून 4 के खंड (8) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी नए कुलपति को अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि निलंबन का आदेश रद्द कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक रिक्ति का सृजन नहीं होगा और निलंबित कुलपति के स्थान पर किसी नए कुलपति को अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 16)

माना गया कि क़ानून 4 का खंड (8) सभी प्रकार की नियुक्ति को कवर करता है, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जिनका संदर्भ खंड (8) में किया गया है और पंजाब सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 14 के साथ पढ़े गए खंड (6) के तहत। कुलाधिपति, जो कुलपति का नियुक्ति प्राधिकारी है, के पास कुलपति को निलंबित करने की शक्ति है क्योंकि रोहतक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 में कोई विपरीत इरादा उपलब्ध नहीं है।

(पैरा 18)

माना गया कि रोहतक विश्वविद्यालय अधिनियम, 197 और क़ानून की योजना से यह काफी हद तक स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि कुलपति के खिलाफ कोई जांच की जानी है, तो यह या तो कुलाधिपति द्वारा या किसी के माध्यम से की जानी चाहिए। उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिस पर उसका (कुलाधिपति का) पूर्ण नियंत्रण है और उस जांच के लंबित रहने के दौरान ही निलंबन का आदेश कानूनी रूप से पारित किया जा सकता है यदि कुलाधिपति संतुष्ट हो कि कुलपति के निलंबन से काम में आसानी होगी। पूछताछ का आयोजन. हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जांच आयोग अधिनियम के तहत एक आयोग जांच नियुक्त नहीं की जा सकती है, सरकार के पास एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति है और आयोग कानूनी रूप से और वैध रूप से उन सभी आरोपों की जांच कर सकता है। जो कि एक कुलपति के विरुद्ध किया गया हो सकता है, लेकिन उस जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए कुलाधिपति कानूनी तौर पर कुलपति को निलंबित करने का आदेश पारित नहीं कर सकता है।

(पैरा 25)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

(ए) याचिकाकर्ता के निलंबन से संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 (अनुलग्नक पी-9) का आदेश, कृपया शून्य होने के कारण रद्द किया जा सकता है;

(बी) कुलाधिपति पी. 20 का आदेश, जिसमें उपायुक्त, रोहतक को विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है, को शून्य होने के कारण रद्द किया जा सकता है;

(सी) चांसलर, प्रतिवादी नंबर 1, को याचिकाकर्ता के खिलाफ विश्वविद्यालय अधिनियम और के प्रावधानों के विपरीत किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी भी मांग को स्वीकार करने से रोका जा सकता है। याचिकाकर्ता की कुलपति के रूप में नियुक्ति के नियम और शर्तें;

(डी) चांसलर, प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता के खिलाफ मनमाने ढंग से कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जा सकता है; अधिनियम और क़ानून के प्रावधानों की अवहेलना में।

(ई) उत्तरदाताओं संख्या 2 से 7 को विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है जैसे कि विश्वविद्यालय में अनुशासन का नियंत्रण;

(एफ) चांसलर प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता के वैधानिक कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है।

(छ) यह घोषित किया जा सकता है कि पहली याचिका के अनुबंध 'पी-4' के अनुसार, याचिकाकर्ता को 28 अक्टूबर, 1977 से छह साल की अवधि के लिए कुलपति के रूप में काम करने का अधिकार है।

अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना

(i) उपायुक्त, रोहतक को राज्य सरकार की मिलीभगत या मदद से याचिकाकर्ता के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है।

(ii) कुलाधिपति, प्रतिवादी संख्या 1 को कार्यवाहक कुलपति के रूप में उपायुक्त, रोहतक की नियुक्ति से संबंधित अपने अमान्य आदेश वापस लेने के लिए कहा जा सकता है।

(iii) याचिकाकर्ता के अवैध निलंबन और कार्यवाहक कुलपति के रूप में उपायुक्त, रोहतक की अवैध नियुक्ति के बाद से, जिनके आदेशों का विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में कोई कानूनी बल नहीं होगा, पूरी तरह से अराजकता और अंतहीन मुकदमेबाजी को जन्म देगा। विश्वविद्यालय, याचिकाकर्ता के निलंबन और उपायुक्त, रोहतक की विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्ति से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन पर इस रिट याचिका का निर्णय होने तक रोक लगाई जा सकती है।

कि पहली याचिका के अलावा, पहली याचिका और इस याचिका में उल्लिखित तथ्यात्मक आधार पर इस माननीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी कोई या समान याचिका दायर नहीं की गई है। अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां याचिका के साथ दाखिल करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है और प्रतिवादियों को अग्रिम प्रतियां भी प्रदान की जा सकती हैं।

सी. विविध. 1979 का 1577.

धारा 151 सी.पी.सी. के तहत विविध आवेदन प्रार्थना है कि याचिकाकर्ता आवेदक को 5 अक्टूबर, 1979 की शाम तक महाधिवक्ता, हरियाणा को प्रतियों की प्रतियां उपलब्ध कराने और 8 अक्टूबर, 1979 की सुबह अदालत में इन्हें दाखिल करने की अनुमति दी जाए, और याचिका कृपया स्वीकार की जाए 9 अक्टूबर 1979 को सुना गया।

सी. विविध. 1979 का 1642.

धारा 151 सी.पी.सी. के तहत विविध आवेदन प्रार्थना करते हुए कि न्याय के हित में और रिकार्ड को दुरुस्त करने के लिए, कृपया उपर्युक्त दस्तावेजों को क्रमशः अनुलग्नक पी-21, 22 और 23 के रूप में रिकार्ड में रखने की अनुमति दी जाए।

धारा 151, आदेश XI नियम 14, आदेश XLI, नियम 27, सी.पी.सी. के तहत आवेदन। प्रार्थना करते हुए कि कृपया ऊपर उल्लिखित दो दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए और याचिकाओं में प्रासंगिक आरोपों के संबंध में उन पर विचार किया जाए।

हरद्वारी लाल, व्यक्तिगत रूप से

प्रतिवादी 1 से 6 के लिए यू.डी. गौड़, ए.जी. (एच)

ज्ञान सिंह, प्रतिवादी संख्या 7 के वकील, हरि परन सिंह, वकील के साथ

निर्णय

न्यायमूर्ति पी. सी. जैन

1) श्री हरद्वारी लाल ने भारत के संविधान की धारा 226 के तहत यह याचिका दायर की और उनके खिलाफ पारित निलंबन के आदेश को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की, दिनांक 21 सितंबर, 1979 (कॉपी अनुलग्नक पी/ 9 याचिका में) और आदेश दिनांक 21 सितंबर, 1 (याचिका में अनुलग्नक पी/20 की प्रति) जिसके द्वारा श्री चंदर सिन आई.ए.एस. डिप्टी कमिश्नर, रोहतक को अस्थायी रूप से वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि चंद लॉर (प्रतिवादी नंबर 1) को याचिकाकर्ता के खिलाफ

किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार से विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों और शर्तों के विपरीत कोई भी डीमा स्वीकार करने से रोका जाए। और याचिकाकर्ता की कुलपति के रूप में नियुक्ति की शर्तें।

(2) याचिकाकर्ता के तर्कों को समझने के लिए, मामले की कुछ मुख्य विशेषताओं को दोहराना आवश्यक होगा जो निम्नानुसार हैं:

(3) याचिकाकर्ता को दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 की अधिसूचना के माध्यम से तीन साल की अवधि के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक का कुलपति नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति की शर्तें अलग से जारी की गईं। याचिकाकर्ता कुलपति बने रहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ समय से विश्वविद्यालय परिसर में काफी अशांति है। याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कारण सरकार और उसके मंत्रियों का अनावश्यक हस्तक्षेप है। जो भी हो, तथ्य तो यही है कि विश्वविद्यालय परिसर में अशांति फैली हुई है।

(4) 11 सितम्बर 1979 को "द ट्रिब्यून" में एक समाचार छपा जिसका आशय यह था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोसली की एक बैठक में कहा था कि याचिकाकर्ता ने छुट्टी पर जाने से इंकार कर दिया है।उसके पास उसे निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो सके।

कुछ नोटिस की आशंका से, याचिकाकर्ता ने उक्त समाचार-आइटम के आधार पर सी.पी.डब्ल्यू. दायर किया। 1979 की संख्या 3228। उस याचिका में 17 सितंबर, 1979 को प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 6 की ओर से अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए थे। याचिका पर सुनवाई हुई और बेंच ने 20 तारीख को सितंबर, 1979 को याचिका को जल्द ही खारिज कर दिया गया। हालाँकि बेंच के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन जिन मामलों पर बेंच ने राय व्यक्त की उनमें से एक यह था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई निलंबन आदेश पारित नहीं किया गया था।

(5) इसके बाद, 21 सितंबर, 1979 को याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आदेश चांसलर द्वारा पारित किया गया; और उपायुक्त, रोहतक को कुलपति नियुक्त किया गया; अस्थायी तौर पर. जैसा कि पहले देखा गया, याचिकाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर इन आदेशों की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया है। 25 सितंबर, 1979 को महाधिवक्ता, हरियाणा को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया और विवादित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई। उत्तरदाताओं ने अलग-अलग लिखित बयान दाखिल किए हैं जिनमें दुर्भावनापूर्ण आरोप सहित भौतिक आरोपों को पूरी तरह से

नकार दिया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने लिखित बयान में याचिकाकर्ता को निलंबित करने की अपनी कार्रवाई का समर्थन किया है।

(7) इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से श्री हरद्वारै लाल द्वारा और प्रतिवादियों की ओर से विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा बहस की गई।

(8) विद्वान याचिकाकर्ता के तर्कों से निपटने से पहले, मैं 1979 के सिविल विविध आवेदन संख्या 1042 और 1979 के सिविल विविध आवेदन संख्या 1700 का निपटान करने का प्रस्ताव करता हूं। इन दोनों आवेदनों की सूचना विद्वान महाधिवक्ता को दी गई थी | 1979 का सिविल विविध क्रमांक 1700 डॉ. एस. उप-आयुक्त, रोहतक को कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने के संबंध में श्री प्रेम भाटिया के दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 को लिखे गए पत्र की एक प्रति, सिविल विविध संख्या, 1642/1970 के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखी जानी है।1979 के सिविल विविध संख्या 1642 के तहत, श्री प्रेम भाटिया के 10 अक्टूबर, 1979 के पत्र की एक प्रति, जो याचिकाकर्ता को लिखी गई थी, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि जिस संवाददाता की रिपोर्ट पर समाचार आइटम दिनांकित है 10 सितंबर 1979, 'द ट्रिब्यून' में छपा, अगर बुलाया जाए तो वह गवाह के रूप में पेश होगा, और रजिस्ट्रार द्वारा याचिकाकर्ता को लिखे गए पत्र की एक प्रति और कुछ प्रेस बयान पेश करने की मांग की गई है। बहस के दौरान हमें इन दस्तावेज़ों की कोई प्रासंगिकता नहीं मिली। परिणामस्वरूप हम इन दो विविध आवेदनों में की गई प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं और उन्हें खारिज करते हैं।

(9) जहां तक प्रतिकृति का सवाल है, हमने याचिकाकर्ता को उसमें से कुछ प्रासंगिक अंशों को पढ़ने की अनुमति दी और उसे नए आरोपों का उल्लेख करने और प्रतिकृति के साथ तैयार किए गए नए दस्तावेजों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी, और इस हद तक कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी।

(10) याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह था कि कुलाधिपति के पास पंजाब जनरल क्लॉज एक्ट (इसके बाद संदर्भित) की धारा 14 के साथ पठित, रोहतक विश्वविद्यालय के प्रथम क़ानून के क़ानून 4 के खंड (6) के तहत उन्हें निलंबित करने की कोई शक्ति नहीं थी। पंजाब अधिनियम के रूप में)। यह पार्टियों का स्वीकृत मामला है कि चांसलर, कुलपति का नियुक्ति प्राधिकारी है और पंजाब अधिनियम की धारा 14 के तहत नियुक्ति करने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को निलंबित करने की भी शक्ति होगी, जब तक कि कोई अलग इरादा न हो प्रकट होता है। याचिकाकर्ता द्वारा तर्क देने की मांग की गई थी कि रोहतक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और क़ानून के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों से यह स्पष्ट था कि कुलाधिपति द्वारा निलंबन की शक्ति के प्रयोग के संबंध में एक विपरीत इरादा दिखाई देता है। याचिकाकर्ता के इस तर्क की सराहना करने के लिए, अधिनियम और क़ानून के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

(11) रोहतक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975, (बाद में इस अधिनियम के रूप में संदर्भित) को 21 अगस्त, 1975 को हरियाणा के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि कुलाधिपति, कुलपति, डीन छात्र कल्याण, रजिस्ट्रार, नियंत्रक, और विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें क़ानून द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जा सकता है, उप-धारा (2) के तहत, कुलाधिपति को यह शक्ति दी गई है कि वह ऊपर उल्लिखित कार्यालयों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को जब भी आवश्यक समझे और ऐसे नियमों और शर्तों पर नियुक्त कर सकता है जो वह उचित समझे। धारा 9 में प्रावधान है कि कुलाधिपति के अलावा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका और कार्य क़ानून और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जहां तक वे निर्धारित नहीं हैं अधिनियम में | धारा 9 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, वह अवधि जिसके लिए वे पद धारण करेंगे और ऐसे कार्यालयों में आकस्मिक रिक्तियों को भरना होगा। जैसे कि क़ानून द्वारा निर्धारित है। रोहतक विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में, परिनियम 2 के तहत यह प्रावधान है कि हरियाणा के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे। क़ानून 3(1) के तहत यह प्रावधान है कि कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा। क़ानून 4 एक महत्वपूर्ण क़ानून है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा बहुत अधिक जोर दिया गया था, इसे पूरी तरह से पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है: -

"4. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति के बाद रैंक लेगा। वह कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में दीक्षांत समारोह और न्यायालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और संबोधित करने का हकदार होगा।

(2) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, क़ानून, अध्यादेश और विनियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए। उसके पास इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी।

(3) कुलपति के पास न्यायालय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और वित्त समिति की बैठक बुलाने की शक्ति होगी और वह ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो अधिनियम, क़ानून के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(4) यदि कुलपति की राय में कोई आपातकालीन स्थिति हो उत्पन्न हुआ जिसके लिए आवश्यक है कि तत्काल कार्रवाई की जाए कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह समझे आवश्यक है और इसकी

पुष्टि के लिए यहां रिपोर्ट करेंगे प्राधिकरण की अगली सफल बैठक जिसमें सामान्य तरीके से मामले को निपटाया जाता:

बशर्ते कि यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है तो वह मामले को कुलाधिपति को भेज सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा:

बशर्ते कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रभावित करती है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी सूचना देने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राथमिकता देने का अधिकार होगा। कार्रवाई प्राप्त होती है, कार्यकारी परिषद में अपील।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करेगा।

(6) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर की जाएगी।

(7) कुलपति सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

(8) कुलपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में, कुलाधिपति। नए कुलपति की नियुक्ति होने तक अस्थायी नियुक्ति कर सकते हैं।"

क़ानून 5 में प्रावधान है कि प्रति-कुलपति ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा जो समय-समय पर कुलपति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा। खंड (2) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि प्रति-कुलपति की सेवा की शर्तें और नियम ऐसे होंगे जो कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(12) उपरोक्त प्रावधानों की समीक्षा से, यह स्पष्ट है कि कुलपति विश्वविद्यालय का एक अधिकारी है जिसे क़ानून में निर्धारित कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं और उसकी नियुक्ति सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जानी है। कुलाधिपति द्वारा निर्धारित ऐसे नियमों और शर्तों पर, और कुलाधिपति को भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता होती है।

(13) अब, मैं याचिकाकर्ता के विवाद के गुणों से निपटने का प्रस्ताव करता हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले यह देखा जा सकता है कि श्री हरद्वारी लाल ने यह प्रस्तुत करके अपनी दलीलें शुरू की थीं कि पंजाब अधिनियम की धाराएं अधिनियम के प्रावधानों पर लागू नहीं होतीं। हरद्वारी लाल कुलपति बनाम चांसलर एम.डी. विश्वविद्यालय और अन्य (पी.सी. जैन, जे.) और क़ानून, लेकिन उन्होंने डॉ. बूल चंद बनाम चांसल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (1) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर इस विवाद पर जोर नहीं दिया। इसलिए, मामले को इस आधार पर आगे बढ़ाना होगा कि पंजाब अधिनियम की धारा 14 अधिनियम और क़ानून के प्रावधानों पर लागू होती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अधिनियम और क़ानून के जिन प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था, उनमें कुलाधिपति द्वारा निलंबन की शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई विपरीत इरादा दिखाई देता है। माना जाता है कि, चांसलर नियुक्ति प्राधिकारी है और पंजाब अधिनियम की धारा 14 के तहत उसके पास कुलपति को निलंबित करने की शक्ति होगी जब तक कि कोई विपरीत इरादा इंगित न किया गया हो।

(14) याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया था कि क़ानून 4 के खंड (6) के तहत, कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा उसके द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर की जाती है; खंड (7) के तहत कुलपति आमतौर पर तीन साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है और खंड (8) के तहत आकस्मिक रिक्ति के मामले में, कुलाधिपति के पास एक नया कुलपति नियुक्त करने की शक्ति है , नए कुलपति की नियुक्ति तक, अस्थायी रूप से। श्री हरद्वारी लाल के अनुसार, जब परिनियम 4 के खंड (6), (7) और (8) को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि खंड (6) के तहत नियुक्ति के बाद खंड (7) के साथ पढ़ा जाता है। यदि कोई व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए कुलपति के रूप में कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति उस अवधि के लिए कुलपति बना रहता है और कुलाधिपति किसी भी तरह से उसके (कुलपति के) कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, क़ानून केवल क़ानून 4 के खंड (8) के तहत प्रदान किए गए तरीके से एक आकस्मिक रिक्ति को भरने का प्रावधान करता है; कि आकस्मिक रिक्ति केवल मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्यथा के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आती है; अधिनियम की धारा 8 के तहत केवल एक कुलपति की नियुक्ति की जा सकती है और निलंबन का आदेश पारित करने से कोई रिक्ति नहीं बनती है, कि जब एक कुलपति पद पर बना रहता है तो किसी अन्य कुलपति की नियुक्ति नहीं की जा सकती; जिस क्षण नियमित नियुक्ति खंड (6) के तहत खंड (7) में प्रदान की गई अवधि के लिए, या कुछ अन्य नियमों और शर्तों पर की जाती है, तो ऐसी नियुक्ति के संबंध में कुलाधिपति की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जिस अवधि के लिए उसे नियुक्त किया गया है, उस अवधि तक कुलपति के रूप में बने रहने का उसे अपरिहार्य अधिकार है; यह अनसुना नहीं है क्योंकि संविधान के तहत की गई कुछ नियुक्तियों के मामलों में, निलंबन की कोई शक्ति नहीं है,और यह सही है कि निलंबन की शक्ति का अधिनियम या क़ानून में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि चांसलर और वाइस-चांसलर के बीच स्वामी और नौकर का कोई संबंध नहीं है।

(15) पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, हम याचिकाकर्ता के इस तर्क से सहमत होने में खुद को असमर्थ पाते हैं।

(16) शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि क़ानून 4 के खंड (8) का मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। खंड (8) आकस्मिक रिक्ति होने पर अस्थायी रूप से कुलपति की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ऐसी नियुक्ति नये कुलपति की नियुक्ति तक ही होती है। आकस्मिक रिक्ति तब होती है जब वह किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर अस्तित्व में आती है, अर्थात मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्यथा। आकस्मिक रिक्ति होती है और बनाई नहीं जाती। यदि ऐसा है, तो निलंबन के आदेश के परिणामस्वरूप कोई आकस्मिक रिक्ति अस्तित्व में नहीं आएगी क्योंकि निलंबन के आदेश के परिणामस्वरूप केवल कार्यालय, पद या किसी के विशेषाधिकार से अस्थायी रूप से वंचित होना पड़ेगा। निलंबन आदेश के परिणामस्वरूप कोई पद रिक्त नहीं होता है। निलंबन का प्रभाव केवल उस व्यक्ति से उस कार्य को छीनना है जो उससे करना अपेक्षित है। यदि निलंबन के आदेश से कोई रिक्ति सृजित नहीं होती है, तो क़ानून 4 के खंड (8) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी नए कुलपति को अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले को देखते हुए, निष्कर्ष से बचना संभव नहीं है कि निलंबन के आदेश के परिणामस्वरूप आकस्मिक रिक्ति का सृजन नहीं होगा और निलंबित कुलपति के स्थान पर किसी नए कुलपति को अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(17) उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या क़ानून में कोई अन्य प्रावधान है जो निलंबन की शक्ति के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। मौजूदा मामले में, निलंबन की शक्ति का प्रयोग पंजाब अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित क़ानून 4 के खंड (6) के तहत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क देने की मांग की गई थी कि खंड (6) केवल सामान्य या नियमित नियुक्तियों के मामलों पर लागू होता है और यह पद को अस्थायी रूप से भरने के लिए नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करने की परिकल्पना नहीं करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, क़ानून ने रिक्तियों को अस्थायी रूप से भरने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया था और यदि मामला उस प्रावधान, यानी खंड (8) के अंतर्गत नहीं आता है, तो किसी भी स्थिति में अस्थायी रूप से नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मेरी राय में, याचिकाकर्ता का तर्क फिर से अस्थिर है। खंड (6) और (8) को पढ़ने से पता चलता है कि वे एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले देखा है, खंड (8) केवल अस्थायी आकस्मिक रिक्ति के आवेदन पर लागू होता है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति क़ानून (4) के खंड (यू) के तहत की गई थी। कुलाधिपति उसका नियुक्त प्राधिकारी है। पंजाब अधिनियम की धारा 14 के तहत, प्राधिकारी को तब तक निलंबित करने की शक्ति है जब तक कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो जाए। विपरीत इरादे का पता लगाने के लिए खंड (8) के प्रावधानों से कोई लाभ नहीं लिया जा सकता क्योंकि वही पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र को कवर करता है। यह उचित रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यदि कोई मामला खंड (8) के

प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है, तो किसी भी स्थिति में अस्थायी नियुक्ति या कुलपति को इस तरह के विवाद के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, यदि स्वीकार किया जाता है , असंगत और अतार्किक परिणाम दे सकता है। मैं एक उदाहरण लेकर इस पहलू को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ। किसी दिए गए मामले में, एक कुलपति किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से अक्षम हो सकता है। अक्षमता इतनी है कि वह कोमा की स्थिति में है. डॉक्टरों की राय में ऐसी स्थिति करीब एक महीने तक बनी रहने की संभावना है. यदि श्री हरद्वारी लाल का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुलाधिपति के पास एकमात्र विकल्प विकलांग कुलपति को हटाना होगा। प्रथम दृष्टया यह न केवल अमानवीय लग सकता है बल्कि बेतुका भी लग सकता है। इस बात पर सहमति हुई और जाहिर तौर पर यह सही भी है कि यह स्थिति खंड (8) में शामिल नहीं है। ऐसा होने पर, विश्वविद्यालय के कार्यों को पूरा करने के लिए कुलपति को अस्थायी रूप से नियुक्त करना कुलाधिपति का दायित्व बन जाएगा और यह क़ानून 4 के खंड (6) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। यदि खंड (6) क़ानून 4 को इस दृष्टि से देखा जाए तो निलंबन की जो समस्या हमारे सामने है उसका उत्तर बहुत आसान हो जाएगा। चांसलर नियुक्ति प्राधिकारी है और किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए, यदि कार्रवाई अन्यथा उचित हो, तो वह क़ानून 4 के खंड (6) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग करने का हकदार होगा। श्री हरद्वारी लाल ने तर्क दिया था कि दो कुलपति नहीं हो सकते क्योंकि अधिनियम की धारा 8 में केवल एक कुलपति की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है। याचिकाकर्ता का यह दृष्टिकोण फिर से एक स्पष्ट भ्रांति से ग्रस्त है। धारा 8 केवल यह निर्धारित करती है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी कौन होंगे और कुलपति उनमें से एक है। यही हाल कुलाधिपति कार्यालय का भी है | जब किसी कुलपति को निलंबित कर दिया जाता है या किसी अन्य तरीके से कुलपति के रूप में काम करने में अक्षम कर दिया जाता है और यदि कोई अन्य अस्थायी नियुक्ति की जाती है तो उस अवधि के लिए केवल एक ही कुलपति होता है जो वास्तव में उस कार्यालय के कार्यों का निर्वहन कर रहा होता है और वह धारा 8 के प्रावधानों का आशय यही है। दूसरे शब्दों में, धारा 8 के तहत एक कुलपति होना चाहिए जो वास्तव में उस कार्यालय के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो। जैसा मैंने पहले देखा है, धारा 8 के तहत चांसलर भी विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होता है। वर्तमान मामले में, राज्यपाल विश्वविद्यालय के एक्स- ऑफिशल चांसलर हैं | मान लीजिए कि राज्यपाल एक महीने का अर्जित अवकाश लेता है और उसके स्थान पर एक कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वह (कार्यवाहक राज्यपाल) स्वचालित रूप से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बन जाएगा। जो राज्यपाल अर्जित अवकाश पर चला गया है, वह कुलाधिपति नहीं रहेगा। यदि श्री हरद्वारी लाल का तर्क स्वीकार कर लिया जाए तो कुलाधिपति के मामले में भी छुट्टी पर जाने वाले राज्यपाल (कुलाधिपति) को एक माह के लिए कुलाधिपति पद से हटाना होगा और उसके बाद ही दूसरे कुलाधिपति की नियुक्ति की जा सकेगी। मेरे विचार में, यह न तो संभव है और न ही ऐसा करने का इरादा है। जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 8 में केवल उस व्यक्ति के पदनाम का उल्लेख है जो विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा और इस प्रावधान से यह नहीं माना जा सकता है कि नियमित पदधारी के मामले में किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से

कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अपने कार्यालय के कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ। श्री हरद्वारी लाल ने तर्क दिया था कि क़ानून के तहत ही कुलपति को अपने कुछ कर्तव्यों को प्रो-वाइस-चांसलर या रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को सौंपने की शक्ति है और किसी भी घटना में जहां कुलपति अस्थायी रूप से होता है अपने कार्यों को करने में असमर्थता की पूर्ति शक्तियों को प्रत्यायोजित करके की जा सकती है। इस तर्क से याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिलती, न ही मिलती है। यह उस उदाहरण से मेल खाता है जो मैंने निर्णय के पहले भाग में लिया है। इसके अलावा, अधिनियम और क़ानून के तहत, कुलपति अपनी कुछ शक्तियों को सौंपने की स्थिति में हो सकता है जो विश्वविद्यालय के कामकाज को सुविधाजनक बना सकता है लेकिन अधिनियम या क़ानून में कोई प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया जिसके तहत कुलपति - चांसलर विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को कुलपति के रूप में कार्य करने का निर्देश दे सकता है |

[0:35 am, 20/12/2023] Chahat: (18) मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि क़ानून 4 का खंड (6) सभी प्रकार की नियुक्तियों को कवर करता है, सिवाय उन नियुक्तियों को छोड़कर जिनका खंड (8) में संदर्भ दिया गया है और खंड (6) के तहत। , पंजाब अधिनियम की धारा 14 के साथ पढ़ें, कुलाधिपति, जो कुलपति का नियुक्ति प्राधिकारी है, को निलंबित करने की शक्ति है क्योंकि अधिनियम या क़ानून में कोई विपरीत इरादा उपलब्ध नहीं है। (19) श्री हरद्वारी लाल ने अगला तर्क दिया कि यदि हम उनके पहले तर्क पर सहमत नहीं हैं कि अधिनियम के तहत कुलाधिपति के पास कुलपति को निलंबित करने की कोई शक्ति नहीं है, तो चांसलर द्वारा निलंबन की इस शक्ति का प्रयोग केवल एक जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है, जो या तो स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त कुछ व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जाती है। याचिकाकर्ता के अनुसार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (इसके बाद इसे जांच के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत नियुक्त आयोग द्वारा की जाने वाली जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए निलंबन का आदेश पारित नहीं किया जा सका। अधिनियम) इस प्रकार निलंबन केवल राज्य सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए होगा। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि निलंबन का आदेश पारित करने से पहले चांसलर की व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए; निलंबन का आदेश केवल तभी पारित किया जाना चाहिए जब इससे अंततः नियुक्ति प्राधिकारी को हटाने का आदेश पारित करने में मदद मिलेगी और जांच अधिनियम के तहत आयोग द्वारा कोई भी निष्कर्ष कुलाधिपति के लिए कोई मदद या सहायता नहीं करेगा जैसा कि अंततः कुलाधिपति ने किया है निलंबन का आदेश पारित करने से पहले अपनी स्वतंत्र राय बनाने के लिए |

20) दूसरी ओर, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में आयोग की नियुक्ति जांच अधिनियम के तहत की गई थी; आयोग द्वारा कुलपति के खिलाफ उन आरोपों के संबंध में जांच की जा रही थी जो उनके खिलाफ लगाए गए थे; कि कुलाधिपति के कहने पर सरकार द्वारा जांच आयोग नियुक्त किया गया था और ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता के खिलाफ

निलंबन का आदेश पारित करना सही था। विद्वान वकील के अनुसार, एक बार जब निलंबन की शक्ति कुलाधिपति में स्वीकार कर ली जाती है, तो आयोग द्वारा जांच कराने की सुविधा के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी रूप से निलंबन का आदेश पारित किया जा सकता है।

(21) पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के तर्क में काफी दम है। मौजूदा मामले में, आयोग को जांच अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त किया गया है, जो इस प्रकार है: -

"3. (1) उपयुक्त सरकार ऐसा कर सकती है। यदि उसकी राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, और यदि इस संबंध में एक प्रस्ताव लोक सभा द्वारा पारित किया जाता है या, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा। राज्य की विधान सभा, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने और निष्पादन करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करती है। ऐसे कार्य और ऐसे समय के भीतर जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और इस प्रकार नियुक्त आयोग जांच करेगा और तदनुसार कार्य करेगा:

बशर्ते कि जहां किसी भी मामले की जांच के लिए ऐसा कोई आयोग नियुक्त किया गया हो-
(ए) केंद्र सरकार द्वारा, कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना, इसकी जांच के लिए किसी अन्य आयोग की नियुक्ति नहीं करेगी। जब तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा है तब तक मामला;

(बी) किसी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार उसी मामले की जांच के लिए किसी अन्य आयोग को तब तक नियुक्त नहीं करेगी जब तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा है, जब तक कि केंद्र सरकार की राय न हो कि जांच का दायरा होना चाहिए दो या दो से अधिक राज्यों तक विस्तारित किया जाए।

(2) आयोग में उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं, और जहां आयोग में एक से अधिक सदस्य होते हैं, उनमें से एक को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(3) उपयुक्त सरकार, आयोग द्वारा जांच के किसी भी चरण में, आयोग के सदस्य के कार्यालय में उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति को भर सकती है, चाहे वह एक या एक से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हो)।

(4) उपयुक्त सरकार रिपोर्ट (यदि कोई हो) लोक सभा या, राज्य की विधान सभा (जैसा भी मामला हो) के समक्ष रखेगी। उप-धारा (1) के तहत आयोग द्वारा उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने की अवधि के भीतर उस पर की गई कार्रवाई के एक ज्ञापन के साथ।"

(22) जांच अधिनियम की धारा 3 को पढ़ने से पता चलता है कि आयोग को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है और उसे अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। कुलाधिपति का आयोग से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है. आयोग के नियमों और शर्तों को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। यहां यह उपयोगी होगा कि धारा 7 के तहत सरकार के पास यह घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है कि उसकी राय में आयोग की निरंतरता अनावश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचना की तारीख से आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आयोग ने यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई कर भी सकती है और नहीं भी. किसी दिए गए मामले में रिपोर्ट पर प्रकाश भी नहीं डाला जा सकता है। कुलाधिपति के पास सरकार से आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति उसे भेजने के लिए कहने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब जांच अधिनियम के तहत एक आयोग नियुक्त किया जाता है, तो यह संभव हो सकता है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लंबा समय लग सकता है और इस स्थिति में चांसलर, जिनके कहने पर आयोग नियुक्त किया गया था, एक असहाय दर्शक बने रहेंगे।

(23) अधिनियम और क़ानून में विश्वविद्यालय के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, जिसका नेतृत्व चांसलर करता है। विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है और सरकार का एक विभाग नहीं है। सामान्यतः यह सरकार के किसी भी प्रकार के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। जहां तक विश्वविद्यालय के मामलों का सवाल है, कुलाधिपति केवल नाममात्र का प्रमुख नहीं है और उसे महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और विश्वविद्यालय के मामलों में उसकी प्रभावी भूमिका होती है। चांसलर की शक्तियों को समझने के लिए, क़ानून और अधिनियम में कुछ प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है। क़ानून 4 के खंड (4) के तहत यदि कुलपति द्वारा की गई कोई कार्रवाई कार्यकारी द्वारा अनुमोदित नहीं होती है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है। अधिनियम की धारा 15(5) के तहत. प्रत्येक नए क़ानून या क़ानून में परिवर्धन या किसी क़ानून में किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी जो मंजूरी दे सकता है। इसे अस्वीकार करें या आगे विचार के लिए भेज दें। इसी प्रावधान के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा पारित किसी क़ानून की तब तक कोई वैधता नहीं होगी जब तक उस पर कुलाधिपति की सहमति न हो | अधिनियम की धारा 19(1) के तहत कुलाधिपति के पास किसी भी समय, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम और क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता या निर्देश देने की शक्ति है। उसके तहत बनाए गए अध्यादेश और विनियम। और यदि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उपधारा (2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि इसे किसी भी सिविल न्यायालय में

प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह सच है कि कुलपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है और यह काफी प्रतिष्ठा और अधिकार रखता है। कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है।

(24) यदि इस पृष्ठभूमि के साथ हम आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान कुलपति को निलंबित करने की कुलाधिपति की कार्रवाई की वैधता का आकलन करते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगी।

(25) जैसा कि पहले देखा गया है, कुलाधिपति केवल एक नामधारी प्रमुख नहीं है। अधिनियम और क़ानून के तहत उन्हें विश्वविद्यालय के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं। नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते उसके पास कुलपति को हटाने या निलंबित करने की शक्ति है, लेकिन ऐसी कार्रवाई करने से पहले उसे अकेले ही खुद को संतुष्ट करना होगा कि उस शक्ति के प्रयोग के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। कुलपति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निलंबन की शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए और वह भी केवल वहीं जहां कदाचार, भ्रष्टाचार या अनैतिकता के कुछ गंभीर और गंभीर आरोप लगाए गए हों, जो जांच में साबित होने पर परिणाम हो सकते हैं। कुलपति को हटाना. यदि वर्तमान प्रकृति के किसी मामले में निलंबन की शक्ति भी स्वीकार कर ली जाती है, तो किसी भी स्थिति में इससे बड़ी कठिनाई और अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। वर्तमान मामले को उदाहरण के रूप में लेते हुए, मान लीजिए कि जांच लगभग एक वर्ष तक चलती है और अंततः जांच से कुछ भी नहीं निकलता है, तो याचिकाकर्ता का निलंबन केवल एक सजा होगी क्योंकि जब तक जांच समाप्त होगी तब तक उसका शेष बचे अवधि समाप्त भी हो सकती है आयोग की रिपोर्ट से निलंबित व्यक्ति को क्या सांत्वना या राहत मिलेगी, भले ही वह सभी आरोपों से बरी हो गया हो, जबकि शरारत पहले ही की जा चुकी हो। अधिनियम की योजना और क़ानून से, मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि कुलपति के खिलाफ कोई जांच की जानी है, तो यह या तो कुलाधिपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए। जिस पर उनका (कुलाधिपति का) पूर्ण नियंत्रण है, और उस जांच के लंबित रहने के दौरान ही निलंबन का आदेश कानूनी रूप से पारित किया जा सकता है यदि कुलाधिपति संतुष्ट हो कि कुलपति के निलंबन से जांच आयोजित करने में सुविधा होगी जाँच करना। हालाँकि, हमारे इस निष्कर्ष का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि जाँच अधिनियम के तहत कोई आयोग नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सरकार के पास एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति है और आयोग कानूनी रूप से और वैध रूप से उन सभी आरोपों की जांच कर सकता है जो याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए हों, लेकिन उस जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए चांसलर कानूनी तौर पर निलंबन का आदेश पारित नहीं कर सके। (26) यह मुझे याचिकाकर्ता के अगले तर्क पर लाता है कि चांसलर की विवादित कार्रवाई दुर्भावना से ग्रस्त है। श्री हरद्वारी लाल द्वारा यह तर्क देने की कोशिश की गई थी कि निलंबन का आदेश चांसलर की व्यक्तिगत दुर्भावना के परिणामस्वरूप और हरियाणा

के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल की राजनीतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आया है। जहां तक दुर्भावना के आरोप के समर्थन में तथ्यों के बयान का सवाल है, यह देखना उचित होगा कि याचिका में, समय की कमी के कारण, इस तरह से आरोप लगाए गए हैं कि यह बन गया है इसे सीधे कालानुक्रमिक या उचित तरीके से बताना काफी कठिन है। इस याचिका को दायर करते समय, याचिकाकर्ता ने अपनी पिछली याचिका (सिविल रिट याचिका संख्या 3226/1979) को इस याचिका के हिस्से के रूप में माना है, जिसे इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 20 सितंबर, 1979 को खारिज कर दिया था। बहुत प्रयास करने के बाद ही दोनों याचिकाओं में वर्णित द्वेष के आरोप की कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने रखी जा रही हैं।

(27) जैसा कि इस याचिका के पैराग्राफ 3 से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता ने कुछ ऐसे कारण सामने लाए हैं जो विश्वविद्यालय परिसर में रुक-रुक कर होने वाली अशांति के लिए जिम्मेदार हैं। वे कारण इस प्रकार हैं:-

"(ए) हरियाणा राज्य सरकार के कहने पर और श्री एम.एल. बत्रा की इच्छा के विरुद्ध, प्रतिवादी नंबर 1 के पूर्ववर्ती-कार्यालय द्वारा नियुक्त डॉ. जे.डी. सिंह, प्रो-वाइस-चांसलर, एम.डी. विश्वविद्यालय की साज़िशें याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती और राज्य सरकार के कहने पर और उसके (प्रतिवादी नंबर 1) व्यक्तिगत और दुर्भावनापूर्ण कारणों से, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 21 सितंबर, 1979 तक बरकरार रखा गया। इस संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाता है पहली याचिका के अनुलग्नक पी-3, पी-5 और इस याचिका के भाग 2 के पैरा 9 के लिए।

(बी) सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, जैसा कि पहली याचिका के अनुलग्नक पी. 7, 11, 12, 13, 14 और 28 में दर्शाया गया है, विशुद्ध रूप से दुर्भावनापूर्ण कारणों से।

(सी) विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और मंत्रियों या सरकार द्वारा याचिकाकर्ता की अनुचित बदनामी, जैसा कि इस याचिका और पहली याचिका के अनुबंध -7, 11, 12, 13, 14 और 28 में बाद में दर्शाया गया है।

(डी), स्वामी अग्निवेश, प्रतिवादी संख्या 4, श्री मेहर सिंह राठी, प्रतिवादी संख्या 5, श्री मंगल सेन, प्रतिवादी संख्या 6 और श्री हीरा नंद आर्य, प्रतिवादी संख्या 7 के याचिकाकर्ता के खिलाफ पुरानी दुश्मनी और उनकी मांग याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय से हटाने से विश्वविद्यालय परिसर पर बहुत ही अस्थिर प्रभाव पड़ा है (पहली याचिका के अनुलग्नक पी-10, पी-11, पी-12, पी-13, पी-27)।

(ई) इस याचिका के प्रतिवादी नंबर 1 चांसलर द्वारा याचिकाकर्ता को इतना वश में रखने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में अशांति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया गया कि वह अपनी अनुचित व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा कर सके। इस संबंध में, इस याचिका के अनुबंध पी-1 और पहली याचिका के पी-5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।" बहस के दौरान, हमें उन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से अवगत कराया गया, जिन्हें याचिकाकर्ता ने अपने तर्क के समर्थन में रिकॉर्ड पर रखा है कि चांसलर की विवादित कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। जहां तक कुलाधिपति का सवाल है, श्री हरद्वारी लाल ने हमारा ध्यान कुलाधिपति को संबोधित अपने दिनांक 12 अगस्त, 1979 के पत्र की ओर आकर्षित किया, जिसकी प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 13 के रूप में संलग्न की गई है इस पत्र में , विभिन्न तथ्य बताए गए हैं जो दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता अपनी इच्छाओं को पूरा करके चांसलर को उपकृत कर रहा है। इस पत्र में प्रति-कुलपति के रूप में डॉ. जे.डी. सिंह की नियुक्ति का भी जिक्र किया गया है, जिनके साथ कुलपति की नहीं बन रही है. याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए फ़ाइल में समाचार पत्रों की कुछ कटिंग भी लगाई हैं कि जब से उन्हें विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है, तब से कोई न कोई मंत्री विश्वविद्यालय में उनके काम में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहा है और उत्पात मचा रहा है। परिसर में अशांति. याचिकाकर्ता ने यह भी बताने की कोशिश की है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल सत्ता में बने रहने और विश्वास मत जीतने की कोशिश कर रहे हैं; 1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 3228 दाखिल करने से पहले, कोसली में उनके (हरियाणा के मुख्यमंत्री) द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता को निलंबित किया जा रहा है; कि याचिकाकर्ता को उस स्टेटमेंट पर उक्त रिट याचिका को पेश करनेलिए मजबूर किया गया था, अंततः रिट याचिका को समयपूर्व के रूप में खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह उत्तरदाताओं को रोक दिया गया था कि सस्पेट्सुन ना पीन का कोई आदेश पारित या विचार नहीं किया गया था; और याचिका को खारिज कर दिया गया था और 21 नवंबर, 1979 को चांसलर द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। याचिका में जो पेश करने की मांग की गई थी, वह यह था कि 20 सितंबर, 1979 से पहले, जो भी अधिनियम मौजूद थे, वे पर्याप्त नहीं थे क्योंकि कुछ भी नहीं लाया गया था। यह दर्शाने के लिए कि याचिकाकर्ता का निलंबन विचाराधीन था, पहले लिखित विवरण दिया गया था; इस फ़ाइल में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि चांसलर के पास क्या नई सामग्री उपलब्ध थी, जिसके निलंबन का आदेश 21 सितंबर, 1979 को पारित किया गया था, या याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करने वाले इस न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद। सीमा, और ये सभी तथ्य यह साबित करते हैं कि चांसलर की कार्रवाई ने कुछ बाहरी विचारों को प्रभावित किया है। जैसा कि मैंने पहले देखा है कि याचिकाकर्ता ने द्वेष की दलील को साबित करने के लिए हमें उन सभी सामग्रियों से अवगत कराया जिन पर वह निर्भर था। यहां तक कि उन्होंने कुछ विविध आवेदन दायर करके रिकॉर्ड पर सामग्री लाने की भी कोशिश की, जिसका संदर्भ मैंने अपने जजमेंट के पहले भाग में दिया है।

(28) जवाब में, कुलाधिपति, मुख्यमंत्री और मंत्रियों, जिनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं, ने स्पष्ट रूप से आरोपों से इनकार किया है।चांसलर, प्रतिवादी नंबर 1, ने लिखित बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सितंबर, 1979 के स्थगन आदेश के पहले और बाद में प्राप्त प्रतिनियुक्तियों और पत्रों/प्रस्तुतियों के संचयी प्रभाव के रूप में, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने प्रामाणिक रूप से एक राय बनाई कि मामले की परिस्थितियां और आरोपों की प्रकृति यह मांग करती है कि याचिकाकर्ता को कुलपति के रूप में काम करना जारी रखना उचित नहीं होगा क्योंकि यह आवश्यक हो सकता है उनके अधीन काम करने वाले लोगों से तथ्यों का पता लगाना या उन मामलों की जांच करना जो उनकी हिरासत में हैं और यह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए दुलत आयोग के समक्ष सच सामने लाने के लिए शर्मनाक और उपयुक्त होगा, जबकि याचिकाकर्ता मौके पर नाराज था और कुलपति के रूप में कार्य करना, और फिर निलंबन आदेश का आश्वासन दिया और कहा कि याचिकाकर्ता के निलंबन का आदेश सरकार के कहने पर पारित नहीं किया गया था, प्रतिवादी नंबर 1 ने दुर्भावना के आरोपों से इनकार किया, याचिकाकर्ता ने उन्हें प्रमाणित करने की मांग की रिकॉर्ड पर कुछ दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए, जबकि दूसरी ओर, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने भी यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा किया कि द्वेष की दलील निराधार थी। विद्वान महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि याचिका में पैराग्राफ 4 में दी गई दलील यह है कि श्री भजन लाल ने याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए चांसलर, प्रतिवादी नंबर 1 से आग्रह किया या दबाव डाला; इस कथन को साबित करने के लिए इस रिकॉर्ड पर बिल्कुल भी कोई सामग्री नहीं है और यह न्यायालय द्वेष के इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि यह एक विवादित तथ्य का प्रश्न मुद्दा बन गया है।

(29) पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, हमें विद्वान महाधिवक्ता के इस तर्क में काफी बल मिलता है कि दुर्भावना के आरोपों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे तथ्य का एक विवादित प्रश्न उठाते हैं। यह देखना उचित होगा कि दुर्भावना के अधिकांश भौतिक आरोप जो पिछली याचिका में लगाए गए थे और जो इस याचिका का हिस्सा थे, बेंच द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने तथ्य का एक विवादित प्रश्न उठाया था। सम्मानपूर्वक, हम पीठ के उस निष्कर्ष से सहमत हैं। इस मामले में हमने जो पाया है वह यह है कि यदि इस विवादित प्रश्न पर जाने का प्रयास भी किया जाए, तो विस्तृत साक्ष्य दर्ज करने के बाद भी किसी न किसी तरह से आरोपों की सत्यता निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है। अखबार की कटिंग, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है, को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और सामंत एन बालकृष्ण आदि बनाम जॉर्ज फर्नांडीज और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अन्य (2), जिसमें यह इस प्रकार देखा गया है:-

"गवाहों के माध्यम से वास्तव में क्या हुआ था इसके किसी भी सबूत के बिना एक समाचार आइटम का कोई महत्व नहीं है। यह सबसे अच्छा एक सेकेंड-हैंड सेकेंडरी सबूत है। यह सर्वविदित है कि

पत्रकार जानकारी एकत्र करते हैं और इसे संपादक को देते हैं जो समाचार संपादित करता है आइटम और फिर उसे प्रकाशित करता है। इस प्रक्रिया में सच्चाई विकृत हो सकती है या विकृत हो सकती है। ऐसी खबरों को खुद को साबित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, हालांकि अगर अन्य सबूत जबरन हैं तो उन्हें अन्य सबूतों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है।"

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम दुर्भावना के विवादित आरोपों के गुण-दोष पर जाने से इनकार करते हैं।

श्री हरद्वारी लाल ने निम्नलिखित तर्क भी उठाए:-

(i) कि श्री चंदर सिंह, उपायुक्त, रोहतक को कानूनी रूप से अस्थायी रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है;

(ii) कि याचिकाकर्ता को छह साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जारी रहना था; और

(iii) कि कुलपति के विचारों को जाने बिना कुलाधिपति द्वारा किसी प्रति-कुलपति की नियुक्ति नहीं की जा सकती। बिंदु संख्या, (ii) और (iii) पर विचार करने लायक नहीं है क्योंकि इस याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, ये बिंदु विचार के लिए बिल्कुल भी नहीं उठते हैं। जहां तक बिंदु संख्या (i) का संबंध है, ऐसे मामले में जहां जांच होनी है, कुलाधिपति द्वारा प्रयोज्य निलंबन की शक्ति के संबंध में हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर गुण-दोष के आधार पर उससे निपटना आवश्यक नहीं है। जांच अधिनियम के तहत नियुक्त एक आयोग द्वारा आयोजित। (3) विद्वान महाधिवक्ता के प्रति पूर्ण निष्पक्षता में, हम इस आशय की उनकी प्रारंभिक आपत्ति पर ध्यान देने का प्रस्ताव करते हैं कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी राहत का हकदार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि उसके साथ कोई प्रत्यक्ष अन्याय हुआ है। हमें डर है, इस मामले की परिस्थितियों में, हमें इस आपत्ति में कोई योग्यता नहीं दिखती। यह मानने के बाद कि आयोग द्वारा जांच कराने की सुविधा के लिए चांसलर कानूनी तौर पर निलंबन का आदेश पारित नहीं कर सकते, इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि इस तरह के आदेश से निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के साथ अन्याय होगा। इस प्रकार, प्रारंभिक आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(31) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

(1) रोहतक विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के परिनियम 4 का खंड (6), उन नियुक्तियों को छोड़कर सभी प्रकार की नियुक्तियों को कवर करता है जिनका संदर्भ खंड (8) में किया गया है; पंजाब

अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित खंड (6) के तहत, चैनलर, जो नियुक्ति प्राधिकारी है, के पास कुलपति को निलंबित करने की शक्ति है, और अधिनियम या क़ानून में कोई विपरीत इरादा उपलब्ध नहीं है;

(2) कि कुलपति को कुलाधिपति द्वारा केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब जांच स्वयं (चांसलर) या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से की जानी हो जिस पर (चांसलर) का पूर्ण नियंत्रण हो, और यह केवल है उस जांच के लंबित रहने के दौरान कानूनी तौर पर निलंबन का आदेश पारित किया जा सकता है यदि कुलाधिपति संतुष्ट हो कि कुलपति के निलंबन से जांच कराने में सुविधा होगी; और

(3) दुर्भावनापूर्ण आरोपों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वे तथ्य के विवादित प्रश्न उठाते हैं।

(32) हमारे निष्कर्ष संख्या (2) के मद्देनजर, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और 21 सितंबर 1979 के निलंबन के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं। परिशिष्ट पी 9, चांसलर, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी. 20, जिसके द्वारा श्री चंदर सिंह, उपायुक्त, रोहतक को अस्थायी रूप से कुलपति नियुक्त किया गया था, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा